in which the World Bank had also invested about Rs. 400 crores;

(c) if so, what is Government's reaction thereto; and

(d) the steps taken by Government to improve the functioning of the Port?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) A World Bank Team visited the Port in Oct. 91. The report of the team has not yet been received.

(b) and (c) Does not arise.

(d) A number of steps have been taken to improve the functioning of the Port including the following:

(1) Intensive training of employees

(2) Intensive marketing of port facilities

(3) Improvement of infrastructural facilities

(4) Regular interaction with users

(5) Stepping up the construction of the National Highway leading to the Port.

(6) Opening of a Container Freight Station at Kalamboli and Chembur addition to the one in the Port.

इंडियन एयरलाइन्स को उड़ानों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता

*146. **श्री शिवाजीराव राजाराव पाटिल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में परोसे जाने वाले भोजन के स्तर में काफी गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भोजन की आपूर्ति करने वाली एजेंसी अत्यधिक ऊंचे दाम वसूलने के बावजूद निम्नस्तरीय भोजन की आपूर्ति करती है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रतियोगी आधार पर निविदाएं आमंत्रित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर परोसे गए भोजन के लिये ठेकों को, टेण्डरों की समीक्षा के आधार पर प्राप्त दरों और तत्पश्चात् आवश्यक समझे जाने पर, कीमत निर्धारण के लिये की गई बातचीत के आधार पर ही अंतिम रूप दिया जाता है।

(ङ) भोजन की गणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(1) गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से अर्हता प्राप्त खान-पान कर्मचारियों द्वारा उड़ान-पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण जांच और खान-पान संस्थापनों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है ;

(2) जिन स्थानों पर भोजन तैयार किया जाता है, स्टोर किया जाता है, पूर्व-व्यवस्थित किया जाता है और लादा जाता है वहां समुचित स्वच्छता की स्थितियां सुनिश्चित करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा खान-पान संस्थापनों/यूनिटों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(3) जब भी खामियां ध्यान में आती हैं खान-पान प्रबन्धकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है ।

भारतीय पोत परिवहन निगम को हुआ घाटा

*147. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पोत परिवहन निगम में सरकार का कुल पूंजी निवेश कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पोत परिवहन निगम पिछले अनेक वर्षों से लगातार घाटा उठा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो निगम को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है, और क्या सरकार ने घाटे को नियंत्रित करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार ने भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में अब तक 261.23 करोड़ रु. की कुल शेयर पूंजी विनियोजित की है।

(ख) जी, नहीं । भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड 1984-85 से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

*148. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक ऐसी परियोजना की बढ़ी हुई लागत कितनी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि संबद्ध विभागों/मंत्रालयों ने लागत में हुई वृद्धि के कारण इन कोयला परियोजनाओं का विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्तमान में प्रत्येक 20 करोड़ तथा इससे ऊपर की लागत की क्रियान्वयन अधीन 54 कोयला खनन परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और 17 परियोजनाएं पूरा होने के मामले में कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं।

(ग) कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(घ) और (ङ) संशोधित लागत अनुमानों पर अन्तर-मंत्रालयीय समूह में विचार-विमर्श किया जाता है और सार्वजनिक निवेश बोर्ड में प्रयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है सरकार को संशोधित लागत अनुमानों की स्वीकृति संबंधी सिफारिश प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वृद्धि के कारणों की समीक्षा तथा उन पर विचार-विमर्श किया जाता है ।